RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

DPR No. N-193
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 19 JULY TO 25 JULY 2023 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 08 ■ अंक 44 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

कैसे चलेगी भारत की इलेक्ट्रिक गाड़ी? चीन और हॉन्ग कॉन्ग से आ रहा 96 प्रतिशत लीथियम
Page 2

मूवी देखने जा रहे तो अब भी स्नैक्स पर देना पड़ सकता है 18 प्रतिशत जीएसटी
Page 3

अडानी बदलेंगे एशिया के सबसे बड़े स्लम की तस्वीर
Page 4

editoria!

स्टार्टअप से उम्मीद

केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने उम्मीद जतायी है कि भारत में अगले चार-पांच वर्षों में स्टार्टअप कंपनियों की संख्या में दस गुना वृद्धि होगी. उन्होंने कहा है कि भारत में तकनीकी क्षेत्र में बड़ा बदलाव आ रहा है. इस क्षेत्र से जुड़े भारतीय युवाओं का ध्यान पहले सूचना प्रौद्योगिकी पर केंद्रित था. लेकिन, वे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब - 3 और डीप टेक जैसी नयी उभरती तकनीकों के क्षेत्र में सफलता से कदम बढ़ा रहे हैं. राजीव चंद्रशेखर पहले भी भारत में युवाओं के लिए तकनीकी क्षेत्र में अपार संभावनाओं का जिक्र करते रहे हैं. पिछले दिनों एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि भारत में अभी 104 यूनिकॉर्न और एक लाख स्टार्टअप हैं. उन्होंने इसे एक शुरुआत भर बताते हुए कहा था कि देश में एक लाख यूनिकॉर्न और 10 से 20 लाख स्टार्टअप शुरू होने की संभावना है. हाल के वर्षों में स्टार्टअप और यूनिकॉर्न कंपनियों की खूब चर्चा होती है. स्टार्टअप दरअसल ऐसे उद्यम होते हैं जो किसी भी नए आयडिया को लेकर शुरू किए जाते हैं. इनका लक्ष्य बहुत तेजी से विस्तार कर बड़ी कंपनी में बदल जाना होता है. अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि कुछ युवाओं ने मिलकर कोई छोटा स्टार्टअप शुरू किया, और फिर किसी विदेशी दिग्गज कंपनी ने या तो उसे खरीद लिया या उसमें भारी निवेश कर दिया. और रातों-रात युवा उद्यमी अमीर हो गए. इन्हीं स्टार्टअप कंपनियों में सबसे कामयाब कंपनियां यूनिकॉर्न कंपनियां बन जाती हैं. दुनियाभर में एक अरब डॉलर या उससे अधिक मूल्य की कंपनियों को यूनिकॉर्न कहा जाता है. भारत में ओला, बायजू, स्विगी, ओयो सबसे बड़ी यूनिकॉर्न कंपनियों में गिनी जाती हैं. लेकिन, स्टार्टअप कंपनियों की कामयाबी से दमकती कहानियों का एक स्याह पहलू भी है. सफलता की कहानियों के बीच ऐसी भी कहानियां सुनाई दी हैं जब स्टार्टअप बैठ गए और निवेशकों के पैसे डूब गए. एक अध्ययन के अनुसार भारत में 10 में से केवल एक कंपनी 10 साल तक टिक पाती है. मीडिया में आई रिपोर्टों के अनुसार पिछले वर्ष भारत में 2000 से ज्यादा स्टार्टअप बंद हो गए. दरअसल, जल्दी और बड़ी कामयाबी के लिए की जाने वाली किसी भी कोशिश में जोखिम भी उतना ही बड़ा होता है. स्टार्टअप से शानदार कामयाबी तभी मिल सकती है जब इसकी शुरूआत पक्की तैयारी और आने वाली चुनौतियों को भांप कर की जाए. स्टार्ट अप कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती कारोबार में टिके रहने की होती है. स्टार्टअप कंपनियों की कामयाबी की कहानियों को साझा करने के साथ-साथ उनकी नाकामयाबी से मिले सबकों पर भी गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए.

RBI और UAE सेंट्रल बैंक के बीच रुपया-दिरहम में लेन-देन शुरू करने को लेकर बड़ा समझौता

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) सेंट्रल बैंक के बीच शनिवार को स्थानीय मुद्राओं में सीमापार लेनदेन शुरू करने के लिए एक व्यवस्था बनाने और भुगतान एवं संदेश प्रणालियों को एक-दूसरे से जोड़ने के लिए समझौते किए गए। इस आशय के समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर प्रधानमंत्री मोदी की यूएई यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए। एमओयू पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास और यूएई सेंट्रल बैंक के गवर्नर खालेद मोहम्मद बलामा ने हस्ताक्षर किए। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी मौजूद थे। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि ये एमओयू दोनों देशों के केंद्रीय बैंक रुपये और दिरहम का सीमापार लेनदेन में इस्तेमाल बढ़ाने के लिए एक ढांचा खड़ा करने और दोनों देशों की भुगतान प्रणालियों यूपीआई एवं आईपीपी को एक-दूसरे से जोड़ने के लिए सहयोग करने से संबंधित हैं।

भारत अमेरिकी डॉलर में होने वाले कारोबार पर निर्भरता कम करने के लिए स्थानीय मुद्राओं में लेनदेन को बढ़ावा देने की कोशिश में लगा हुआ है। इसी क्रम में कई देशों के साथ रुपये में कारोबार शुरू किया गया है। आरबीआई ने कहा, 'दोनों एमओयू का उद्देश्य निर्बाध सीमापार लेनदेन एवं भुगतान की सुविधा प्रदान करना और दोनों देशों के बीच अधिक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है।

भारत और यूएई के बीच स्थानीय मुद्राओं में कारोबार करने से संबंधित समझौता ज्ञापन में एक स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली (एलसीएसएस) भी स्थापित करने का इरादा जताया गया है। इससे भारतीय रुपये और यूएई दिरहम दोनों का द्विपक्षीय इस्तेमाल बढ़ेगा। आरबीआई ने कहा, 'एलसीएसएस के गठन से निर्यातक और आयातक अपनी संबंधित स्थानीय मुद्राओं में बिल बनाने और भुगतान करने में सक्षम बनेंगे। इससे भारतीय रुपये और यूएई दिरहम विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार का विकास होगा। इस व्यवस्था से दोनों देशों के बीच निवेश और प्रेषण को भी बढ़ावा मिलेगा।

आरबीआई ने कहा कि समझौता ज्ञापन में चालू खातों के सारे लेनदेन और स्वीकृत पूंजी खाता लेनदेन भी शामिल हैं। स्थानीय मुद्राओं में कारोबार शुरू होने से लेन-देन की लागत और निपटान समय में कमी आने के साथ यूएई में रहने वाले भारतीय नागरिकों के स्वदेश पैसा भेजने में भी फायदा होगा। दोनों देशों के केंद्रीय बैंक अपनी त्वरित भुगतान प्रणालियों-यूपीआई और आईपीपी को जोड़ने की दिशा में काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं। इसके साथ दोनों देशों के कार्ड स्विच रुपे और यूएईस्विच को भी जोड़ने पर सहमति जताई गई है।

इसके अलावा दोनों देशों के केंद्रीय बैंक अपनी-अपनी भुगतान संदेश प्रणालियों को संबद्ध करने की भी संभावनाएं तलाशेंगे। इसके तहत भारत की संरचित वित्तीय संदेश प्रणाली (एसएफएमएस) को यूएई की समान प्रणाली से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। आरबीआई ने कहा, 'यूपीआई और आईपीपी को जोड़ने से दोनों देशों के उपयोगकर्ता तेज, सुविधाजनक, सुरक्षित और किफायती ढंग से सीमापार राशि अंतरण कर पाएंगे.' वहीं कार्ड स्विचेज को जोड़ने से घरेलू कार्डों की आपसी स्वीकृति और कार्ड से लेनदेन के प्रसंस्करण में मदद मिलेगी। इसके साथ ही आरबीआई ने कहा कि दोनों देशों की भुगतान संदेश प्रणालियों को जोड़ने से द्विपक्षीय वित्तीय संदेश गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

आरबीआई रेपो रेट पर पर क्या लेगा फैसला? ब्याज ऊपर जाएगा या नीचे?

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आगामी द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा में ब्याज दर के मोर्चे पर यथास्थिति कायम रखेगा। खारा ने बुधवार को भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, ''बैंक के रूप में हम नीतिगत दर में कटौती की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय बैंक यथास्थिति को कायम रखेगा.''रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की अगली बैठक आठ से 10 अगस्त 2023 को होनी है। गत आठ जून की मौद्रिक समीक्षा बैठक में रिजर्व बैंक ने रेपो में लगातार दूसरी बार कोई बदलाव नहीं किया था। हालांकि, इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने कहा था कि वह चाहता है कि मुद्रास्फीति और नीचे आए। बीते महीने थोक मुद्रास्फीति की दर में 4.12 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. इसके साथ इंडेक्स 8 सालों के निचले स्तर पर पहुंच गया है। जून में खुदरा महंगाई दर बढ़ी है, वहीं थोक मुद्रास्फीति में गिरावट दर्ज हुई थी। इस महीने आए आंकड़ों के मुताबिक, रिटेल इंफ्लेशन जिसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) से मापा जाता है, वो मंथ ऑन मंथ बढ़कर 4.81% पर आ गई है। जून एफ्ड 4.25% (मई में) से बढ़कर 4.81% पर पहुंच गया है। सब्जियों की कीमतों में बड़ा उछाल आया है। सब्जियों की महंगाई दर -8.18 पर्सेंट से बढ़कर 0.93% पर पहुंच गई है. खाद्य महंगाई दर 2.96% से बढ़कर 4.49% (MoM) पर पहुंची है। बीते दिन आरबीआई की ओर से जुलाई बुलेटिन में 'India @100' नाम के एक आर्टिकल में कहा गया कि देश को विकसित बनने के लिए 2047 तक 7.6 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर जरूरी है। यानी कि अगर 7.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर रही तो 2047 तक हम एक विकसित देश बन सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के में प्रकाशित एक लेख में यह बात कही गई है। फिलहाल, भारत की वृद्धि दर 2022-23 में 7.2 प्रतिशत थी। चालू वित्त वर्ष के दौरान इसके 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। लेख में यह भी कहा गया कि भारत को अपने औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि आर्थिक संरचना को संतुलित किया जा सके। इसके लिए सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी 2047-48 तक बढ़ाकर 35 प्रतिशत करनी होगी, जो इस समय 25.6 प्रतिशत है।

जी-20 की बैठक में क्रिप्टो करेंसी के लिए नियम बनाने पर चर्चाः सीतारमण

गांधीनगर। एजेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यहां जी-20 बैठक में क्रिप्टो करेंसी के लिये एक व्यापक और समन्वित वैश्विक नीति तथा नियामकीय व्यवस्था बनाने को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि जी-20 के सदस्य देशों ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिये अपनी प्रतिबद्धता दोहरायी। यह समूह दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का अंतर-सरकारी मंच है। सीतारमण गांधीनगर में जी-20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर (एफएमसीबीजी) की तीसरी बैठक समाप्त होने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में यह कहा। उन्होंने कहा कि बैठक में जी-20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर ने लोगों और दुनिया की बेहतरी को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया। साथ ही अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग बढ़ाने, सभी के लिये वैश्विक विकास को मजबूत करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था की मजबूत, संतुलित तथा समावेशी वृद्धि को लेकर प्रतिबद्धता दोहरायी। सीतारमण ने कहा, ''क्रिप्टो करेंसी के लिये एक व्यापक और समन्वित वैश्विक नीति तथा नियामकीय व्यवस्था बनाने को लेकर चर्चा हुई.'' उन्होंने यह भी कहा कि जी-20 की अध्यक्षता कर रहे भारत ने समूह के समक्ष डिजिटल ढांचागत सुविधा के मुद्दे को रखा है। वित्त मंत्री ने कहा, ''भारत ने अपनी अध्यक्षता में डिजिटल ढांचागत सुविधा के एजेंडा को जी-20 की बैठक में उठाया। सदस्यों ने वित्तीय समावेश और उत्पादकता के लाभ को तेजी से आगे बढ़ाने में डिजिटल ढांचागत सुविधा (डीपीआई) की महत्वपूर्ण भूमिका का समर्थन किया। सीतारमण ने कहा कि कर्ज को लेकर बिगड़ती स्थिति पर भी जी-20 सदस्य देशों ने विचार-विमर्श किया। बैठक में खराब होती कर्ज स्थिति को प्रभावी ढंग से निपटने के लिये बहुपक्षीय समन्वय को मजबूत करने और ऋण समस्या से जूझ रहे देशों के लिये समन्वित उपाय किये जाने पर बातचीत हुई। कर्ज समाधान के लिये साझा व्यवस्था तैयार करने पर चीन की प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, 'चीन का रुख उत्साहजनक था।''

News यू केन USE

गूगल पे के नए फीचर में यूजर बिना यूपीआई पिन के कर सकेंगे छोटे भुगतान

नई दिल्ली। एजेंसी

प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल के भुगतान ऐप गूगल पे ने बृहस्पतिवार को अपने मंच पर यूपीआई लाइट फीचर पेश किया, जिससे छोटे डिजिटल भुगतान में आसानी होगी। गूगल ने कहा कि यूपीआई लाइट से उपयोगकर्ता को तत्काल भुगतान के लिए एक दिन में 4,000 रुपये तक जमा करने की सुविधा मिलेगी। इसके तहत उपयोगकर्ता एक बार में अधिकतम 200 रुपये तक का भुगतान कर सकेगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा डिजायन इस फीचर में छोटे भुगतान करने के लिए यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं होती है। गूगल के उत्पाद प्रबंधन के उपाध्यक्ष अंबरीश केंघे ने कहा कि अनुठी सुविधाएं देश में डिजिटल भुगतान की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए जरूरी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यह फीचर सितंबर, 2022 में पेश किया था।

जून में थोक मुद्रास्फीति दर में 4.12 प्रतिशत की गिरावट

नई दिल्ली।एजेंसी

ईंधन एवं विनिर्मित उत्पादों की कीमतें कम होने से जून में थोक मुद्रास्फीति की दर में 4.12 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शुक्रवार को थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी करते हुए यह जानकारी दी। इसके पहले मई में थोक मुद्रास्फीति दर में 3.48 प्रतिशत की गिरावट आई थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जून में खाद्य उत्पादों की मुद्रास्फीति दर में 1.24 प्रतिशत की गिरावट रही जबकि मई में इसमें 1.59 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि हुई थी। ईंधन एवं बिजली खंड की मुद्रास्फीति जून में 12.63 प्रतिशत घट गई जबकि मई में इसमें 9.17 प्रतिशत की कमी आई थी। समीक्षाधीन अवधि में विनिर्मित उत्पादों की थोक मुद्रास्फीति में 2.71 प्रतिशत की गिरावट आई जबकि मई में यह 2.97 प्रतिशत घटी थी। मंत्रालय ने विज्ञप्ति में कहा कि जून के महीने में थोक मुद्रास्फीति की दर में गिरावट आने का मुख्य कारण खनिज तेल, खाद्य उत्पादों, मूल धातुओं, कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस और कपड़ों की कीमतों में आई कमी है।

6 प्रतिशत के करीब जा सकती है रिटेल महंगाई दर : नोमुरा

नई दिल्ली। एजेंसी

ब्रोकरेज फर्म नोमुरा का कहना है कि जिस तेजी से भारत में खाद्य चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, ऐसे में जुलाई में रिटेल महंगाई दर छह फीसदी के आसपास तक जा सकती है। नोमुरा के अनुसार खाद्य चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी वाकई असामान्य है। खाद्य चीजों की तेजी को अस्थायी कहा जा रहा है, मगर यह तेजी कब रुकेगी, कहना मुश्किल है। मौजूदा हालात में लग रहा है कि कीमतों में तेजी का असर अगस्त महीने के रिटेल महंगाई दर को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, RBI की मॉनेटरी पॉलिसी पर इसका क्या असर कहना मुश्किल है। RBI मात्र सब्जियों की कीमतों को देखकर अंतिम फैसला नहीं लेता। ना ही इस मामले में कोई जल्दबाजी करता है। निश्चित तौर पर RBI अभी वेट एंड वॉच की स्थिति को बरकरार रखेगा।

कैसे चलेगी भारत की इलेक्ट्रिक गाड़ी?

चीन और हॉन्ग कॉन्ग से आ रहा 96 प्रतिशत लीथियम

नई दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने हाल में 30 क्रिटिकल मिनरल्स की एक लिस्ट बनाई है। इसमें ऐसे मेटल्स को शामिल किया गया है जो देश की इकनॉमिक ग्रोथ और नेशनल सिक्योरिटी के लिए अहम हैं। इनमें लीथियम भी शामिल है जिसे नए जमाने को गोल्ड कहा जाता है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी, मोबाइल फोन, लैपटॉप, हाइड्रोजन फ्यूल स्टोरेज, एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स और फार्मास्यूटिकल्स में होता है। देश में कई इंडस्ट्रीज इस एक मेटल पर निर्भर हैं लेकिन भारत में अब तक इसका एक किलो भी उत्पादन नहीं होता है।

हाल में जम्मू एवं कश्मीर ने 59 लाख टन लीथियम का भंडार मिला है लेकिन इससे उत्पादन शुरू होने में अभी समय लगेगा। अभी भारत चीन और हॉन्ग कॉन्ग से लीथियम आयन का आयात करता है जिसका इस्तेमाल बैटरी में होता है। 2020-21 में भारत के लीथियम आयात में चीन की हिस्सेदारी 73 परसेंट थी। अगर हॉन्ग कॉन्ग को भी मिला दिया जाए तो यह 96 परसेंट बैठती है। लीथियम के अलावा कोबाल्ट, निकल, वैनेडियम, नियोबियम, जरमैनियम, रेनियम, टैंटालम और स्ट्रोनियम जैसे क्रिटिकल मिनरल्स के लिए भी भारत पूरी तरह आयात पर निर्भर है।साथ ही कॉपर, गैलियम, ग्रेफाइट, फॉस्फोरस, पोटाश, टिन,

टाइटैनियम और टंगस्टन जैसे मेटल्स भी भारत इम्पोर्ट करता है। इनका इकनॉमिक अहमियत बहुत ज्यादा है लेकिन इनके साथ सप्लाई का रिस्क भी जुड़ा है। निजी कंपनियों ने सरकार की पहल का स्वागत किया है लेकिन उनका कहना है कि इसके लिए एक स्पष्ट नीति की जरूरत है।

क्या चाहती है इंडस्ट्री

इनमें से कुछ मेटल्स की डिमांड में भारी तेजी आने की उम्मीद है लेकिन सप्लाई चेन में मामूली बाधा बहुत भारी पड़ सकती है। इससे हाई-टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलिकम्युनिकेशंस, ट्रांसपोर्ट और डिफेंस इंडस्ट्रीज प्रभावित हो सकती है। इंडस्ट्री के अनुमानों के मुताबिक लीथियम की डिमांड में 2020 से 2040 के बीच 42 गुना और कोबाल्ट की डिमांड में 25 गुना तेजी आने की उम्मीद है। इलेक्ट्रिक टू वीलर बनाने वाली कंपनी एथर एनर्जी के सीईओ तरुण मेहता ने कहा कि सरकार ने सप्लाई चेन में रिस्क कम करने के लिए पहला कदम उठाया है। मेटल्स की माइनिंग और रिफाइनिंग के लिए इंडस्ट्रीज को इन्सेंटिव देना चाहिए।

दुनिया में कोबाल्ट, कॉपर, ग्रेफाइट, लीथियम, मैगनीज, निकल और रेयर अर्थ एलिमेंट का कम से कम 55 परसेंट भंडार 15 देशों के पास है। इनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चिली, चीन, कॉन्गो, गैबन, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, न्यू कैलेडोनिया, पेरू, फिलीपींस, रूस, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका शामिल हैं। इनमें से हर मिनरल की नए जमाने की इंडस्ट्रीज में काफी अहमियत है। भारत के पास इसमें से कोई भी मिनरल नहीं है। ऐसे में भारत को नए डिपॉजिट्स खोजने होंगे या विदेशों से गारंटीड सप्लाई सुनिश्चित करनी होगी।

इकनॉमिस्ट प्रवण सेन का कहना है कि भारत को कुछ क्रिटिकल मटीरियल्स का भंडार बनाना चाहिए।

कितनी कम होगी कीमत

सरकारी और इंडस्ट्री के अनुमानों के मुताबिक 2030 तक भारत के ईवी मार्केट के एक करोड़ यूनिट के पार पहुंचने का अनुमान है। 2022 में यह 10 लाख यूनिट था। लेकिन यह तभी संभव होगा जब सप्लाई में कोई बड़ी अड़चन न आए। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स में लीथियम की अहम भूमिका है। लीथियम की आसान और किफायती उपलब्धता से स्टोरेज बैटरीज की कीमत में भी कमी आएगी। इलेक्ट्रिक वीकल की कुल कीमत में 60 फीसदी हिस्सा बैटरी का ही होता है। इसी तरह देश में कॉपर और निकल की रिफाइनिंग से वीकल की कीमत में 15,000 से 20,000 रुपये की कमी हो सकती है।

कोबाल्ट का इस्तेमाल बैटरी के इलेक्ट्रोड्स, टरबाइन इंजन कंपोनेंट्स और ऑटोमोबाइल एयरबैग्स में होता है। इसी तरह निकल की सोलर पैनल, बैटरीज, एयरोस्पेस और डिफेंस एप्लिकेशन तथा ईवी में अहम भूमिका है। भारत इन दोनों का आयात करता है। इन मिनरल्स की प्रोसेसिंग में चीन का दबदबा है। यूरोप भी अब तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। दुनिया में 70 परसेंट कोबाल्ट का उत्पादन कॉन्गो में होता है।

एयर इंडिया और इंडिगो के बाद अब अकासा एयर खरीदेगी बड़ी संख्या में विमान

जल्द इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी होंगी शुरू

नई दिल्ली । एजेंसी

देश में बढ़ती हवाई यात्रियों की संख्या को भुनाने में एयरलाइन कंपनियां कोई कसर नहीं छोड़ना चाहतीं। एयर इंडिया और इंडिगो के बाद अब झुनझुनवाला फैमिली के निवेश वाली एयरलाइन अकासा एयर भी विमानों का बड़ा ऑर्डर देने जा रही है। अकासा एयर के सीईओ विनय दुबे ने कहा है कि एयरलाइन अच्छी तरह से लिक्विड है यानी इसके आप अच्छा-खासा पैसा है। उन्होंने कहा कि एयरलाइन के पास इस साल के आखिर तक तीन डिजिट में विमानों का ऑर्डर देने के लिए पर्याप्त धन है। दुबे ने कहा कि इस एयरलाइन में काफी अधिक तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता है।

अगले महीने पूरा हो जाएगा एक साल

अकासा एयर अगले महीने अपने परिचालन का एक साल पूरा करने जा रही है। इस बारे में दुबे ने कहा, 'हमने अपनी अपेक्षाओं को पूरा किया है।' इस समय एयरलाइन के पास 19 विमान हैं और 20वां विमान उसके बेड़े में इसी महीने शामिल हो सकता है। कंपनी जल्द ही इंटरनेशनल उड़ानें भी शुरू करने के लिए तैयार है।

76 बोइंग विमानों का दिया ऑर्डर

एक इंटरव्यू में दुबे ने कहा, 'मुझे लगता है कि हमारे पास पर्याप्त पैसा है। हमारे पास 72 विमानों और चार अतिरिक्त विमानों का ऑर्डर देने के लिए पर्याप्त पूंजी थी। इसके अलावा इस साल के आखिर तक तीन डिजिट में विमानों का ऑर्डर देने के लिए पर्याप्त पूंजी है।' हालांकि, उन्होंने इस बारे में कोई विशेष वित्तीय विवरण नहीं दिया। एयरलाइन ने 76 बोइंग विमानों का ऑर्डर दिया है।

मई में एयरलाइन के पास थी 4.8 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी

दुबे ने एयरलाइन के बारे में कहा, 'मुझे नहीं लगता कि हम इस बात में उलझे हुए हैं कि हम थोड़ा तेजी से बढ़ेंगे या धीमी गति से। हम स्थिरता चाहते हैं। हम एक ऐसी एयरलाइन बनाना चाहते हैं जो समय की कसौटी पर खरी उतरेगी।' आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मई में अकासा एयर की घरेलू बाजार हिस्सेदारी 4.8 फीसदी थी।

15 से 20 साल में देश में होंगे करीब 2,000 विमान

उन्होंने कहा कि अगले 20 साल 'विमानन क्षेत्र के लिए स्वर्ण युग' होने जा रहे हैं और देश में अगले 15 से 20 साल में करीब 2,000 विमान होंगे और काफी अधिक संख्या में हवाई अड्डे होंगे। दुबे ने कहा, 'हम जिस स्तर पर हैं, वहां बहुत-बहुत खुश हैं। मुझे लगता है कि काफी वृद्धि हो रही है।' एयरलाइन के बेड़े में 20 विमान होने पर वह अंतरराष्ट्रीय परिचालन शुरू कर सकती है।

मूवी देखने जा रहे तो अब भी स्नैक्स पर देना पड़ सकता है 18 प्रतिशत जीएसटी

काम्बो ऑफर पर अभी भी जीएसटी की दर टिकट के बराबर

नई दिल्ली। एजेंसी

सिनेमाहॉल में मिलने वाले महंगे खाने से थोड़ी राहत मिली है। मल्टीप्लेक्स, थिएटर्स में सर्व किए जाने वाले फूड और बेवरेज आइटम्स पर जीएसटी को 18 फीसदी से कम कर 5 फीसदी कर दिया गया है। थिएटर्स में खाने-पीने की चीजों पर लगने वाली जीएसटी दरों में 13 फीसदी की कटौती से आप थोड़ी राहत मिलने वाली है। पहले के मुकाबले सिनेमाघरों में पॉपकॉर्न, पेप्सी, नाचोज, बर्गर आदि खरीदना सस्ता हो जाएगा। लेकिन जीएसटी काउंसिल के फैसले में एक पेंच भी है।जीएसटी काउंसिल ने सिनेमाघरों में मिलने वाले फूड आइटम्स पर जीएसटी घटाकर आपको राहत तो दी है। लेकिन ये राहत आपको तभी मिल पाएगा जब आप थिएटर या मल्टीप्लेक्स में जाकर खाने-पीने की चीज खरीदेंगे। अगर आपको ऑनलाइन मूवी टिकट बुक करने के साथ फूड और ड्रिंक्स का कॉम्बो ऑफर लेने की आदत हैं तो आपको इसका फायदा नहीं मिल सकेगा। मूवी थिएटर्स में मूवी टिकट के साथ फूड और ड्रिंक्स का कॉम्बो ऑफर मिलता है। जीएसटी काउंसिल ने साफ किया है कि कॉम्बो प्लान में मिलने वाले फूड पर टैक्स वहीं रहेगा, जो टिकटों पर लागू है। ऐसे में टिकट बुक करवाते वक्त इसका ध्यान रखें।

टिकट के साथ फूड बुक करवाने से बचें

यानी जब आप अगली बार सिनेमा देखने जाएं तो ऑनलाइन मूवी टिकट बुक करते वक्त कॉम्बो ऑफर से बचें। कॉम्बो ऑफर मतलब जब आप ऑनलाइन ऐप या वेबसाइट से मूवी टिकट बुक करते हैं तो आपको कॉम्बो ऑफर का ऑप्शन मिलता है। टिकट के साथ खाने-पीने की चीजें आप पहले से बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जीएसटी कटौती का फायदा नहीं मिलेगा। दरअसल जीएसटी काउंसिल से स्पष्ट किया है कि 5 फीसदी जीएसटी केवल उन्हीं फूड एंड बेवरेज आइटम्स पर लगेगा, जो थिएटर्स काउंटर्स पर बेचे जाते हैं । जब आप टिकट के साथ खाने-पीने की चीजें बुक करते हैं तो उसका सिंगल बिल बनता है और जीएसटी वहीं लगता है तो मूवी टिकट पर है। यानी 18 फीसदी। ऐसे में अगर आपको सिनेमाघरों में सस्ता पॉपकॉर्न, पिज्जा, नोचोज खानाा या कोल्ड ड्रिंक्स पीना है तो वहां जाकर ऑर्डर करें। पहले से बुक कर कॉम्बो ऑफर वाले फूड आइटम्स पर पुरानी टैक्स ही लगेगा।

ऐसे खरीद सकते हैं सस्ता पॉपकॉर्न

अगर आप काउंटर से या ऑनलाइन मूवी टिकट खरीदकर सिनेमाहॉल में एंट्री करने के बाद वहां लगे फूड काउंटर्स से खाने-पीने की चीजें खरीदते हैं तो आपको उनपर 5 फीसदी ही टैक्स लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि टिकट और खाने का बिल अलग-अलग होगा। यानी थोड़ी स्मार्टनेस दिखाकर आप अच्छी-खासी बचत कर सकते हैं और सिनेमा देखते हुए सस्ते पॉपकॉर्न, बर्गर का मजा ले सकते हैं।

आयकर विभाग में 3 करोड़ से ज्यादा लोग 18 जुलाई तक फाइल कर चुके हैं ITR

नई दिल्ली। एजेंसी

देश में इस समय आयकर भरने वालों के लिए अपना आयकर रिटर्न भरने का समय चल रहा है। 31 जुलाई तक सभी लोगों को अपना-अपना रिटर्न भरना होता है। सरकार कई बार रिटर्न भरने की तारीख बढ़ा देती है। इस बार क्या होता है अभी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अच्छा होता है कि सभी अपना आयकर रिटर्न अंतिम दिनों का इंतजार किए बगैर जल्द से जल्द भर दें। आयकर विभाग ने ट्वीट के माध्यम से बताया है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 7 दिन पहले ही 3 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरे जा चुके हैं। आयकर विभाग ने कहा है कि इस मील के पत्थर तक पहुंचने में हमारी मदद करने के लिए हमारे करदाताओं और कर पेशेवरों के आभारी हैं। उन्होंने आगे बताया है कि निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए 3 करोड़ से अधिक आईटीआर इस साल 18 जुलाई तक दाखिल किए जा चुके हैं, जबकि पिछले साल 25 जुलाई तक 3 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे। आयकर विभाग ने अपने ट्वीट में कहा कि 18 जुलाई, 2023 तक दाखिल किए गए 3.06 करोड़ आईटीआर में से 2.81 करोड़ आईटीआर ई-सत्यापित किए गए हैं यानी 91इ से अधिक दाखिल आईटीआर ई-सत्यापित किए गए हैं। साथ ही यह भी जानकारी आयकर विभाग ने दी है कि ई-सत्यापित आईटीआर में से 1.50 करोड़ से अधिक आईटीआर पहले ही संसाधित (प्रोसेस्ड) हो चुके हैं। आयकर विभाग ने लोगों से अपील की है कि जल्द से जल्द लोग अपने आईटीआर को फाइल कर दें। उन्होंने कहा कि हम गति बनाए रखने की उम्मीद करते हैं और उन सभी से आग्रह करते हैं जिन्होंने निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किया है, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना आईटीआर दाखिल करें।

टमाटर ने बदली किस्मत, महाराष्ट्र के किसान ने कमाए 2.4 करोड़ रुपये

नई दिल्ली। एजेंसी

टमाटर की कीमत में हाल में काफी तेजी आई है और कई शहरों में तो यह 300 रुपये किलो तक पहुंच गया। इसने लोगों की रसोई का बजट बिगाड़कर रख दिया है लेकिन साथ ही कई किसानों की किस्मत भी बदलकर रख दी है। दिल्ली में रविवार को टमाटर की कीमत 178 रुपये किलो थी जो एक जनवरी की तुलना में 700 परसेंट से भी अधिक है। भारी बारिश के कारण टमाटर की सप्लाई में कमी आई है जिससे इसकी कीमत में भारी इजाफा हुआ है। हालत यह है कि सरकार को सब्सिडी पर टमाटर बेचना पड़ रहा है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में स्थिति सामान्य हो जाएगी। लेकिन टमाटर की कीमत में अचानक आई तेजी से कई किसानों की जबरदस्त कमाई हुई है।

भारत सहित 140 देश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए वैश्विक कर समझौते के करीब

गांधीनगर। एजेंसी

अमेरिका, भारत सहित लगभग 140 देश वैश्विक कर नियमों में बदलाव को लेकर एक समझौते के करीब हैं। इस समझौते में प्रावधान है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) को अपने परिचालन वाले देशों में कर का भुगतान करना होगा। यहां जी20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक से इतर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक में अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) के समावेशी ढांचे में 'ऐतिहासिक दो-स्तंभ के वैश्विक कर करार' को अंतिम रूप देने में भारत के प्रयासों की सराहना की। येलेन ने द्विपक्षीय बैठक में कहा, "मेरा मानना है कि हम समझौते के नजदीक हैं। अंतरराष्ट्रीय कराधान प्रणाली में एक बड़े सुधार के तहत भारत सहित लगभग 140 देश वैश्विक कर नियमों में व्यापक बदलाव के लिए सहमत हुए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जहां भी काम करती हैं, वहां वे न्यूनतम 15 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करें। हालांकि, इस करार के लिए संबंधित देशों को सभी डिजिटल सेवा कर और इसी तरह के अन्य उपायों को हटाना होगा और भविष्य में इस तरह के उपाय लागू नहीं करने की प्रतिबद्धता जतानी होगी। सौदे के कुछ पहलुओं... मसलन लाभ आवंटन में हिस्सा और कर नियमों के दायरे जैसे विषय को सुलझाया जाना बाकी है। समझौते के तकनीकी विवरण पर काम पूरा होने के बाद एक व्यापक सहमति वाला करार अस्तित्व में आएगा।

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने पिछले सप्ताह जारी एक परिणाम बयान में कहा कि कुछ क्षेत्रों ने बहुपक्षीय सम्मेलन (एमएलसी) में 'कुछ विशिष्ट वस्तुओं के साथ' चिंता व्यक्त की है। ओईसीडी ने कहा कि इन मुद्दों को हल करने का काम जारी है। भारत जी20 देशों पर यह सुनिश्चित करने के लिए दबाव डाल रहा है कि प्रस्तावित न्यूनतम कर करार का विकासशील देशों पर कोई 'अवांछित प्रभाव' नहीं पड़े। जी20 की कराधान की समावेशी रूपरेखा में विकासशील देशों की सदस्यता एक-तिहाई की है।

अडानी बदलेंगे एशिया के सबसे बड़े स्लम की तस्वीर

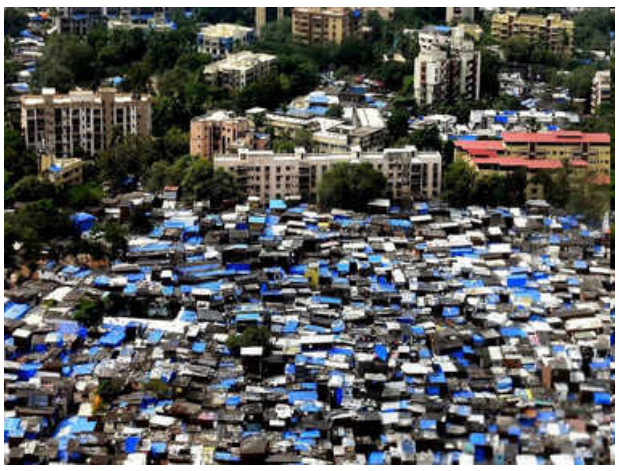

मेकओवर के बाद कैसी दिखेगी धारावी

नई दिल्ली। एजेंसी

एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी, जहां करीब 10 लाख से अधिक लोग रहते हैं। 13000 से अधिक छोटे-मोटे कारोबार चलते हैं, उसकी तस्वीर बदलने वाली है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बीच में बसा दुनिया के घनी आबादी वाले झुग्गियों में से एक धारावी अभावों के बीच सालों से जी रहा है। छोटे-छोटे घर, झुग्गी-झोपड़ी, गंदगी, तंग गलियां इसकी पहचान बन गए हैं। साल 2008 में आई फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर ने दुनिया के सामने धारावी की असली तस्वीर खोलकर रख दी। जिसके बाद से कई बार इसे डेवलप करने की चर्चाएं शुरू हुई, लेकिन हर बार बात अटक गई। लंबे इंतजार के बाद अब देश के बड़े उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी अडानी समूह इसका पुनर्विकास करेगी। पिछले 15 सालों से कई असफल प्रयासों के बाद अब अडानी इसकी सूरत बदलेंगे।

अडानी संवारेंगे धारावी की सूरत

महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई स्थित एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी के पुर्नविकास के लिए अडाणी प्रॉपर्टीज की नियुक्ति को अंतिम मंजूरी दे दी है। अडानी समूह की कंपनी करीब 600 एकड़ के फैले धारावी इलाके के निवासियों के पुनर्वास और उसके रिडेवलपमेंट का काम करेगी। नवंबर 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने धारावी पुर्नविकास परियोजना के लिए टेंडर खोला था। इसके लिए अडानी ग्रुप ने 5069 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी। वहीं अ्ह्र ने 2025 करोड़ रुपये की और नमन ग्रुप ने बोली लगाई थी। अडानी समूह ने सबसे ऊंची बोली लगाकर जीत हासिल की थी।

7 सालों में बदल जाएगी धारावी

सघन आबादी वाले इस इलाकों को अब गौतम अडानी की कंपनी संवारने जा रही है। प्रोजेक्ट के सीईओ एंइ श्रीनिवास के मुताबिक धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जारी कर दिया गया है। इसके लिए जल्द ही लेटर ऑफ अवॉर्ड भी जारी किया जाएगा। इसके बाद ही अडानी समूह इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर सकेगा। इस प्रोजेक्ट को कई चरणों में पूरा किया जाएगा। माना जा रहा है कि पहले चरण की शुरुआत 2024 में हो जाएगी। इस पुनर्वास के लिए परियोजना की कुल समयसीमा 7 साल है। यानी 7 सालों में धारावी की तस्वीर बदल जाएगी। माना जा रहा है कि धारावी रिडेवलपमेंट प्लान के पूरा होने के बाद ये भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। 2.5 लाख वर्म किमी एरिया में रहने वाले करीब 6.5 लाख योग्य लोगों को यहां झुग्गी के बदले फ्लैट दिए जाएंगे। यह परियोजना से 45-47 एकड़ रेलवे भूमि पर बनाई जाने गई झोपड़ियों में रहने वाले लाभार्थियों के सीधे पुनर्वास के साथ शुरू होगी। दूसरी झुग्गी पुनर्वास परियोजनाओं की तरह, इस परियोजना में निर्माण अवधि के दौरान उन्हें अस्थायी घरों में नहीं रखा जाएगा। हालांकि अभी इस प्रोजेक्ट से जुड़ी पूरी डिटेल सामने नहीं आई है।

23000 करोड़ का खर्च

इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 23000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी बनाई गई है। इसके तहत एक स्पेशल पर्पज व्हीकल यानि एइ्र बनाना जाएगा। इस एसपीवी में 80इ्र इक्विटी या 400 करोड़ रुपये होंगे, जिसमें 20इ्र इक्विटी या 100 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी महाराष्ट्र सरकार के पास होगी। एइ्र सर्वे के बाद धारावी में फ्री घर पाने वाले एलिजिबल लोगों की लिस्ट तैयार करेगा। इन लोगों को रिडेवलपमेंट योजना के तहत फ्री में घर दिए जाएंगे। कंपनी को बनाए जाने वाले फ्लैटों के निर्माण के दौरान सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का ध्यान रखना होगा। धारावी को संवारने के लिए पूरा प्लान तैयार है।

फर्जी लोन ऐप वालों की आएगी शामत

आरबीआई उठाने जा रहा ये बड़ा कदम

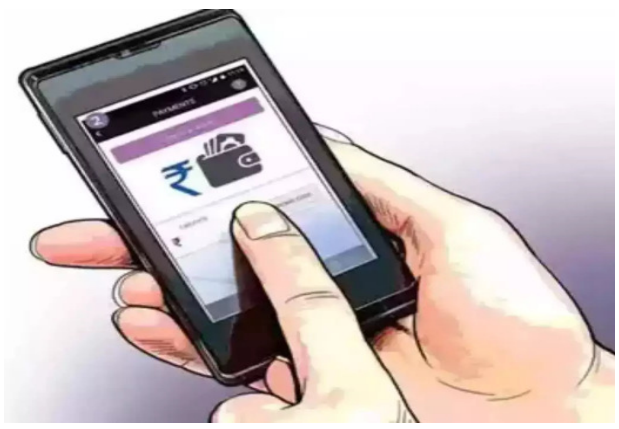

नई दिल्ली। एजेंसी

मार्केट में फैले फ्रॉड ऑनलाइन लोन ऐप के जाल से छुटकारा पाने के लिए RBI एक सिस्टम तैयार करने जा रहा है। इसके तहत जो भी ऐप बैंकिंग रेगुलेटरी सिस्टम के दायरे से बाहर रहकर उधार देने का काम कर रहे हैं, उन्हें इनएक्टिव कर दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार कुछ समय पहले RBI ने गैर बैंकिंग फाइनैंस कंपनियों को उनके ऐप की लिस्ट शेयर करने को कहा था जिसे RBI ने फाइनैंस मिनिस्ट्री के साथ साझा किया था। उसके बाद अवैध तरीके से डिजिटल लोन देने वाले कई ऐप पर कड़ी कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद दोबारा से ऐसे फर्जी डिजिटल लोन ऐप सामने आ गए।

हालांकि, RBI पहले ही कई बार ग्राहकों को चेता चुका है कि ग्राहक रजिस्टर्ड लोन ऐप से ही लोन लें, लेकिन जरूरतमंद ग्राहक अक्सर फर्जी ऐप के जाल में फंस जाते हैं। ऐसे में इनके रिकवरी एजेंट ग्राहकों से न सिर्फ मनमाना ब्याज वसूलते हैं, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करते हैं। गौरतलब है कि RBI 2017 में ही एक सकुर्लर जारी कर ऐसे तमाम ऐप पर कार्रवाई कर चुका है।

बढ़ रहे चंगुल में फंसने के मामले

गौरतलब है कि एक बार फिर देश में चीनी डिजिटल लोन ऐप के चंगुल में फंसने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ऐसे ही एक लोन मुहैया कराने वाले ऐप के एजेंटों की ओर से परेशान किए जाने से बेंगलुरु के 22 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र ने फांसी लगा ली। कथित तौर पर, मृतक छात्र ने 'स्लाइस और किस' चीनी ऐप से पैसे उधार लिए थे जिसे वह चुका नहीं पाया था। ऐसा ही केस कुछ दिनों पहले भोपाल में भी हुआ। वहां तो एक शख्स को लोन की रिकवरी के लिए इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने दो छोटे-छोटे बच्चों और पत्नी समेत आत्महत्या कर ली। ऐसे में अवैध डिजिटल लोन ऐप पर पहले से ही सख्त RBI अब नियमों के इतर उधार देने वाले ऐसे तमाम तरीकों पर लगाम कसने के लिए सिस्टम लाने पर काम कर रहा है।

क्या कहते हैं जानकार?

फाइनैंशल प्लानर कार्तिक झवेरी का कहना है कि RBI पहले ही इन पर बहुत सख्त है, लेकिन हर चीज के लिए सरकार प्रोविजन नहीं कर सकती। सोशल मीडिया के दौर में तो आजकल कई लोग बहुत से ग्रुप बनाकर ब्याज पर पैसा देने-लेने का काम कर रहे हैं, और वे ऐसी किसी एजेंसी को भी हायर कर लेते हैं, जो रिकवरी करे। इसकी एवज में वे इन्हें कमीशन दे देते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि जब भी इस तरह के ऐप से लोन लें और लोन देने वाला बाजार में चल रही उधारी दर से ऊपर कई गुना ब्याज दर मांगे तो तुरंत समझ जाएं कि वह सही प्लैटफॉर्म नहीं है। झवेरी का कहना है कि आजकल बड़े बैंक और NBFC भी पर्सनल लोन सेग्मेंट में सक्रिय हैं। ऐसे में गलत जगह फंसने का कोई मतलब नहीं। यदि आपको प्रताड़ित किया जा रहा है तो आप सायबरक्राइम डॉट जीओवी डॉट इन पर जाकर या फिर 1930 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

ताबड़तोड़ जमा हो रहे हैं 2000 रुपये के नोट

6 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा बैंकों का डिपॉजिट

नई दिल्ली। एजेंसी

19 मई को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 2000 रुपये के नोट को बंद करने के बाद बैंक जमा में वृद्धि हुई। रिपोर्ट के अनुसार जून में 2000 रुपये के नोटों की वापसी के बीच बैंक जमा छह साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया जो बढ़कर 191.6 करोड़ हो गया। इसके बाद से ताबड़तोड़ 2000 रुपये के नोट जमा हो रहे हैं। बैंकों का डिपॉजिट 6 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। 19 मई को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 2000 रुपये के नोट को बंद करने के बाद

बैंक जमा में वृद्धि हुई। रिपोर्ट के अनुसार जून में 2000 रुपये के नोटों की वापसी के बीच बैंक जमा छह साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया जो बढ़कर 191.6 करोड़ हो गया। 19 मई को भारतीय रिजर्व बैंक के 2000 रुपये के नोट को प्रचलन से बाहर करने के बाद बैंको का डिपॉजिट जबरदस्त तरीके से बढ़ा है।

सालाना 13 फीसदी की उछाल

केयर रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक संजय अग्रवाल ने कहा कि 30 जून को समाप्त पखवाड़े में डिपॉजिट में सालाना 13 प्रतिशत की अच्छी वृद्धि देखी गई और यह 191.6 लाख करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले छह वर्षों (मार्च 2017 के बाद से) में सबसे अधिक है जो आंशिक रूप से 2,000 रुपये के करेंसी नोटों की वापसी और जमा पर उच्च ब्याज दरों द्वारा समर्थित है।

क्या कहता है आरबीआई का डेटा?

इस महीने की शुरुआत में, आरबीआई ने कहा था कि 2,000 रुपये के कुल 3.62 लाख करोड़ नोटों में से तीन-चौथाई से अधिक डिपॉजिट (85 प्रतिशत से अधिक) के माध्यम से सिस्टम में वापस आ गए हैं और बाकी नोट एक्सचेंज के रूप में वापस आ गए हैं। समीक्षा अवधि में डिपॉजिट में 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और यह क्रमिक रूप से 3.2 प्रतिशत बढ़कर 191.6 लाख करोड़ रुपये हो गई है। पिछले 12 महीने में डिपॉजिट में कुल 22 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है।

इसके अलावा समीक्षाधीन अवधि में क्रेडिट और जमा वृद्धि के बीच का अंतर नवंबर 2022 में 875 बीपीएस के मुकाबले घटकर 326 आधार अंक रह गया, जो सबसे बड़ा था जिसका कारण दो से तीन पखवड़े में डिपॉजिट में आई तेजी है। पर्सनल लोन, एनबीएफसी और कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के कारण 30 जून को समाप्त समीक्षाधीन पखवाड़े में क्रेडिट ऑफटेक (व्यवसायों और व्यक्तियों द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ली जाने वाली लोन की मात्रा) सालाना आधार पर 16.2 प्रतिशत की दर से बढ़कर 143.9 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। पिछले साल की समान अवधि में क्रेडिट पिकअप 14.5 फीसदी थी।

सैलरी बढ़ाने के लिए बैंक कर्मचारियों ने दिया अल्टीमेटम

बड़े आंदोलन की दी चेतावनी

नई दिल्ली। एजेंसी

बैंकों के करीब आठ लाख कर्मचारी अपनी वेतन बढ़ोतरी को लेकर इस बार आरपार की लड़ाई लड़ने का मन बना चुके हैं। कर्मचारियों की यूनियनों का कहना है कि दिसंबर तक वेतन बढ़ोतरी को लेकर काम पूरा नहीं हुआ है तो फिर वे नए साल से बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो यह सरकार के लिए नई परेशानी खड़ी कर सकता है। बता दें कि अगले लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। सरकार ने भारतीय बैंक संघ (IBA) से कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के लिए 12वें द्विपक्षीय समझौते को लेकर बातचीत की प्रक्रिया शुरू करने और इसे एक दिसंबर तक पूरा करने को कहा है।

वित्त मंत्रालय ने IBA से कहा कि वेतन बढ़ोतरी को लेकर भविष्य में होने वाली सारी बातचीत समय अवधि समाप्त होने से पहले पूरी हो ताकि वेतन संशोधन तय समय पर हो सके। इसके तहत IBA कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत शुरू कर सकता है और आपसी सहमति के आधार पर वेतनवृद्धि को लेकर निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। IBA बैंक के कर्मचारियों से जुड़े मामले, जैसे सैलरी बढ़ोतरी, पेंशन आदि, को सुलझाने का काम करता है। कुछ सरकारी बैंकों के प्रमुख भी इस संगठन के सदस्य हैं। संगठन सरकार और बैंक यूनियनों के बीच पुल का काम करता है।

ठोस बातचीत चाहती हैं बैंक यूनियनें

'बैंक बचाओ, देश बचाओ' मंच के संयोजक सौम्या दत्ता का कहना है कि सरकार हमेशा चुनाव से पहले ही इस तरह के आदेश देती है, लेकिन इसे पूरा करने में दो से तीन साल लग जाते हैं। हम पिछले साल से इस मांग को उठा रहे हैं। बावजूद इसके सरकार ने कुछ ध्यान नहीं दिया। अब लोकसभा चुनावों के पहले सरकार इस मांग पर ध्यान देने की बात क्यों कर रही है। अगर सरकार की सोच और नीयत सही होगी तो जल्द ही इस मामले का समाधान निकलेगा। अगर सरकार ने इस बार फिर झुनझुना थमाने वाली नीति अपनाई तो निश्चित रूप से हम इसके खिलाफ खड़े होंगे। पिछली बार IBA के साथ वेतन में एक और दो फीसदी बढ़ोतरी को लेकर बातचीत शुरू हुई थी। इस बार ऐसा नहीं चलेगा। हम ठोस बातचीत चाहते हैं।

कर्मचारियों को सरकार से काफी उम्मीदें

वाइस ऑफ बैंकिंग के फाउंडर अश्विनी राणा का कहना है कि कर्मचारियों को इस बार सरकार से काफी उम्मीदें हैं। सरकार को इस उम्मीद को बरकरार रखना चाहिए। अगर बैंकिंग सेक्टर का प्रदर्शन अच्छा है तो बैंक कर्मियों के वेतन में अच्छी बढ़ोतरी होनी चाहिए। गौरतलब है कि पिछले समझौते में 12 सरकारी बैंकों, 10 पुरानी पीढ़ी के निजी क्षेत्र के बैंकों और सात विदेशी बैंकों ने साइन किए थे। प्ऽइण बैंक और घ्घ्घ्ध बैंक जैसे नई पीढ़ी के प्राइवेट बैंक इन समझौता वार्ता का हिस्सा नहीं हैं।

राजनीतिक मैदान तक पहुंचा वेतन वृद्धि का मामला?

बैंक कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि नवंबर 2022 को होनी थी, लेकिन अभी तक इस पर बातचीत भी शुरू नहीं हुई। इसे लेकर कर्मचारी सरकार से नाराज हैं। चुनावी साल में सरकार को अब लग रहा है कि ये नाराजगी चुनाव में दिक्कत दे सकती है। इसके चलते सरकार ने IBA से दिसंबर से वेतन वृद्धि पर बातचीत पूरा करके अंतिम समझौता करने को कहा है। लेकिन यह आसान नहीं होगा। वित्त मंत्री ने माना है कि पिछले नौ वर्षों में सरकारी बैंकों के मुनाफे में तीन गुना बढ़ोतरी हुई है। निजी बैंको का प्रदर्शन भी अच्छा रहा। वहीं, महंगाई का मुद्दा भी गरम है। बैंक कर्मचारी की वेतन वृद्धि को लेकर उम्मीदें काफी बढ़ चुकी है। इस मसले पर सरकार थोड़ी फंसी नजर आ रही है। अगर दिसंबर तक यह मसला नहीं सुलझा तो बैंक कर्मचारी की नाराजगी सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकती है।

दिल्ली हवाई अड्डे पर खुला नया एक्सक्लूसिव लाउंज

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

हवाई जहाज का सफर कुछ खास ही होता है। विदेश जाने वाले रूट पर तो यह सफर और खास हो जाता है। अंतरराष्ट्रीय रूट पर जो हवाई जहाज उड़ते हैं, उनमें से अधिकतर में बिजनेस और फर्स्ट क्लास की व्यवस्था होती है। इस क्लास में यात्रा करने वालों के लिए हवाई अड्डे पर विशेष लाउंज की व्यवस्था होती है। इन्हीं यात्रियों के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के टी3 पर आज एक एक वर्ल्ड क्लास बिजनेस क्लास लाउंज खोला गया है। दिल्ली एयरपोर्ट को चलाने वाली कंपनी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने टर्मिनल 3 पर एक वर्ल्ड क्लास बिजनेस क्लास लाउंज खोला है। इस लाउंज का नाम 'Encalm Privé,' दिया गया है। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 स्थित इंटरनेशनल डिपार्चर टर्मिनल पर आज एक विशेष लाउंज खोला गया। इस लाउंज को विशेष तौर पर बिजनेस और फर्स्ट क्लास ट्रेवलर्स के लिए बनाया गया है। दुनिया के विभिन्न एयरपोर्ट पर जाएं तो आपको एक से एक प्रीमियम सुविधाएं मिलेंगी। अब भारत में भी इस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं।इस समय यह लाउंज 22,000 स्केयर फीट में फैला है। बाद में इसका विस्तार 30,000 स्केयर फीट में किया जाएगा। डायल का कहना है कि यह भारत का सबसे बड़ा लाउंज है। इस लाउंज में सभी शाही सुविधाएं जुटाई गई हैं। कुछ क्रेडिट कार्ड पर लाउंज एक्सेस की विशेष सुविधा होती है। ऐसे क्रेडिट कार्ड धारक इस लाउंज का उपयोग नहीं कर सकेंगे। उनके लिए अलग से व्यवस्था होगी। इस लाउंज में बच्चों के खेलने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है।

फॉक्सकॉन कर रही 8800 करोड़ रुपये का निवेश

लगाएगी मैन्युफैक्चिरिंग प्लांट, 14 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

नई दिल्ली। एजेंसी

आईफोन को असेंबल करने वाली कंपनी फॉक्सकॉन कर्नाटक में 8,800 करोड़ रुपये के निवेश से सप्लीमेंट्री प्लांट लगाएगी। कर्नाटक के उद्योग मंत्री एम बी पाटिल ने बताया कि यह प्लांट राज्य के देवनहल्ली इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट रीजन (घ्ऊईं) में लगाया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस सिलसिले में फॉक्सकॉन इंडस्ट्रियल इंटरनेट (एफआईआई) के ण्ईं ब्रैंड चेंग और अन्य प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। पाटिल ने कहा कि इस निवेश प्रस्ताव के तहत फॉक्सकॉन की सहयोगी एफआईआई ने 8,800 करोड़ रुपये के निवेश की योजना रखी है। इससे 14,000 नौकरियां सृजित होंगी।

परियोजना के लिए करीब 100 एकड़ भूमि की जरूरत होगी। एफआईआई, फोन के लिए जरूरी उपकरण बनाने के अलावा स्क्रीन और बाहरी कवर का भी निर्माण करेगी। यह देवनहल्ली (घ्ऊईं) में असेंबली यूनिट के पूरक प्लांट के रूप में काम करेगा। गौरतलब है कि कर्नाटक सरकार ने इस बात के संकेत दे दिये थे कि वह इस प्रोजेक्ट को किसी भी तरह से गवाना नहीं चाहती। वह पूरा प्रयास करेगी कि बातचीत के जरिए इस प्रोजेक्ट की राह में आ रही बाधाओं को दूर किया जाए।

इस साल फॉक्सकॉन और उसकी सहायक कंपनियों की ओर से कर्नाटक को दिया गया यह दूसरा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है। कंपनी ने इसी साल मार्च में एक फोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने के लिए बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल रीजन को चुना है, यहां कंपनी 8,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। इस यूनिट के प्रोपोज्ड इन्वेस्टमेंट के साथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अप्रैल 2024 से चालू होने की उम्मीद है। बता दें कि फॉक्सकॉन हाल ही में तब खबरों में थी, जब वेदांता के साथ गुजरात में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने की उसकी डील कैंसिल हो गई थी। उस समय के रिपोर्ट्स से जानकारी मिली थी कि वेदांता चिप्स बनाने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी हासिल करने में असमर्थ रही। इसके चलते डील में लगातार देरी हो रही थी।

सहारा में फंसा है आपका पैसा 45 दिनों में मिलेगा वापस, जानिए क्या है तरीका

नई दिल्ली। एजेंसी

सहारा की स्कीम में लोगों की जमापूंजी कमाई फंसी हुई है। सालों के लाखों निवेशकों का पैसा सहारा में फंसा है। अब इन निवेशकों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने पोर्टल जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सहारा के 10 करोड़ निवेशकों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए सीआरसीएल-सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च कर दिया। सहारा के करोडों निवेशक अब इस पोर्टल के जरिए घर बैठे अपना पैसा वापस पा सकेंगे। लंबे इंतजार के बाद उन्हें अपना पैसा वापस मिल सकेगा। जानिए कैसे आप इस पोर्टल के जरिए आवेदन कर सहारा में फंसे पैसे वापस पा सकते हैं? कैसे आवेदन करें, कहां आवेदन करें , किन दस्तावेजों की होगी जरूरत और कितने दिनों में आपको रिफंड मिल जाएगा?

सहारा रिफंड पाने के लिए शर्तें

सहारा का रिफंड पाने के लिए आपको सबसे पहले ण्ईं सहारा रिफंड पोर्टल' पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके साथ ही जरूरी है कि आपका मोबाइल फोन आपके आधार से लिंक हो। अगर आपने अपना मोबाइल फोन बदला है तो नए नंबर को आधार से लिंक कर लें। इसके साथ ही जरूरी है कि आपका आधार नंबर आपके बैंक अकाउंट से भी लिंक हो। अगर आपके पास सारे कागज हैं तो आप इस पोर्टल पर जाकर अपनी रसीद अपलोड करके रिफंड पा सकते हैं। सुब्रत रॉय सहारा ने सहारा की शुरुआत कर इसे देश में सबसे बड़े कर्मचारियों वाली कंपनी बना दी, लेकिन कंपनी ने निवेशकों को बड़ा झटका दे दिया।

सूरत के डायमंड एक्सचेंज ने अमेरिका के पेंटागन को छोड़ा पीछे, बनी दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग

अहमदाबाद। एजेंसी

अभी तक दुनिया में सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग का खिताब अमेरिका के रक्षा विभाग के मुख्यालय भवन पेंटागन के नाम रहा है। इस बिल्डिंग में सबसे ज्यादा कर्मचारी काम करते थे। लेकिन अब सूरत में 4 साल की लागत से तैयार हुए सबसे बड़े डायमंड एक्सचेंज ने अमेरिका के पेंटागन को पीछे छोड़ दिया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बन गई है। इस इमारत का आधिकारिक उद्घाटन इस साल नवंबर में किया जा सकता है। सूरत को दुनिया की रत्न राजधानी के रूप में जाना जाता है जहां दुनिया के 90 प्रतिशत हीरे तराशे जाते हैं।

ऐसा बताया जा रहा है कि इस इमारत में 65,000 से अधिक हीरा प्रोफेशनल्स काम कर सकेंगे। इसमें पॉलिशर्स, कटर्स और व्यापारी आदि शामिल होंगे। इसे वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में बनाया गया है। इस इमारत को सूरत डायमंड बोर्स नाम दिया गया है। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, 15 मंजिला इमारत 35 एकड़ भूमि में फैली हुई है और इसमें नौ आयताकार बिल्डिंग्स है जो सभी एक सेंट्रल स्पाइन से जुड़ी हुई हैं। विशाल परिसर का निर्माण करने वाली कंपनी के अनुसार, इसमें 7.1 मिलियन वर्ग फुट से अधिक फ्लोर स्पेस शामिल है।

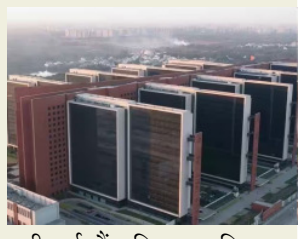

बता दें कि सूरत में दुनिया के 90 फीसदी हीरे तराशे जाते हैं। इस बिल्डिंग में 131 एलिवेटर्स और दूसरी फैसिलिटीज भी हैं। इस प्रोजेक्ट से मुंबई से आने वाले हजारों कर्मचारियों को मदद मिलेगी। एसडीबी यानी कि सूरत डायमंड एक्सचेंज एक गैर-लाभकारी एक्सचेंज है, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनी है। ये बिल्डिंग सूरत और गुजरात में डायमंड बोर्स की स्थापना और प्रचार के लिए बनाई गई है। इस आफिस कॉम्प्लेक्स में एक मनोरंजन क्षेत्र और पार्किंग क्षेत्र है जो 20 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है। नया भवन परिसर हजारों लोगों को व्यवसाय करने के लिए शानदार अवसर देगा। इस इमारत के बनने से पहले ही हीरा कंपनियों ने अपने-अपने ऑफिस खरीद लिए थे। इस बिल्डिंग को एक अंतरराष्ट्रीय डिजाइन प्रतियोगिता के बाद भारतीय वास्तुकला फर्म मॉर्फोजेनेसिस द्वारा डिजाइन किया गया है। इस इमारत को बनने में पूरे 4 साल का समय लगा है। इसे नई दिल्ली स्थित भारतीय वास्तुकला फर्म मॉर्फोजेनेसिस द्वारा डिजाइन किया गया है। जानकारी के मुताबिक, इन परियोजनाओं की लागत करीब 32 अरब रुपये है।

शुक्रवार को सफेद चीजे दान करने से मिलता है मनचाहा फल, मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा

हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन किसी ने किसी देवी-देवता को समर्पित है. ऐसे ही शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है. मान्यता है कि शुक्रवार के दिन विधि-विधान से देवी लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. इस दिन कुछ चीजों का दान बहुत शुभ माना जाता है. आइए आज हम आपको भोपाल निवासी ज्योतिषाचार्य विनोद सोनी पोद्दार के मुताबिक बताते हैं कि शुक्रवार को क्या दान करना चाहिए.

डॉ. संतोष वाधवानी
रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन प्रदेश प्रवक्ता

शक्कर: शुक्रवार के दिन सफेद चीजें दान करना बहुत शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इससे देवी लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं. शुक्रवार को शक्कर दान करने से देवी लक्ष्मी भक्तों के जीवन में खुशियां भर देती हैं. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. आप भी शुक्रवार को शक्कर दान कर सकते हैं.

आटा: अन्न दान बहुत शुभ माना जाता है. इससे घर में सुख-समृद्धि होती है. शुक्रवार के दिन भी अन्न दान करना चाहिए, लेकिन अगर आप इस दिन सफेद अन्न का दान करें तो यह बेहद शुभ होता है. शुक्रवार को आटा दान करने से मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं. इससे घर में सुख-शांति का वास होता है. धन संपदा में वृद्धि होती है. आप भी शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की विधिवत पूजा के बाद जरूरतमंदों को आटा दान करें.

सफेद वस्त्र: शुक्रवार को मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा की जाती है. उनको उनकी पसंदीदा चीजें जैसे कमलगट्टा, लाल फूल, सफेद मिठाई या खीर अर्पित किया जाता है. इसके बाद अगर आप सफेद वस्त्र का दान करें तो यह बहुत शुभ माना जाता है.

दही: शुक्रवार को दही का दान करना बहुत शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं. आटा दान करने से मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं.

चावल: शुक्रवार को आप चावल भी दान कर सकते हैं. मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना के बाद आप अन्न दान के रूप में चावल का दान करें. यह बेहद शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इससे घर का अन्न भंडार भरा रहता है. मां लक्ष्मी अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखती हैं. आप भी शुक्रवार को विधिवत पूजा-अर्चना के बाद चावल जरूर दान करें.

श्रृंगार का सामान चढाएं: शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी का व्रत भी रखा जाता है. इससे देवी लाक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं. शुक्रवार को मां लक्ष्मी को श्रृंगार के सामान अर्पित करने चाहिए. आप उन्हें चूड़ियां, कुमकुम, सिंदूर, साड़ी आदि अवश्य चढ़ाएं. अगर ये लाल रंग की हों तो और शुभ मानी जाती हैं. ऐसा करने से जीवन की सारी परेशानियां दूर होती हैं.

जानें क्या है पार्थिव शिवलिंग का महत्व, ऐसे किया जाता है निर्माण

डॉ. आर.डी. आचार्य
9009369396
ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
इंदौर (म.प्र.)

सावन मास को भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है और इस दौरान शिवलिंग की विशेष तौर पर पूजा की जाती है। शिव पुराण में सावन माह में भगवान शिव व शिवलिंग की पूजा विधि के बारे में विस्तार से बताया गया है। साथ ही पार्थिव शिवलिंग की पूजा के महत्व के बारे में भी बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से कष्टों का नाश होता है और श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है।

ऐसे किया जाता है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण

सावन माह में शिवलिंग की पूजा का संकल्प लेकर किसी पवित्र जगह का चयन करें और पवित्र नदी या सरोवर की मिट्टी लेकर आए। मिट्टी के शुद्धिकरण के लिए फूल और चंदन का प्रयोग करें। मिट्टी के शुद्धिकरण के दौरान शिवमंत्रों का जाप करते हुए मिट्टी में गाय का दूध, गाय का गोबर, गुड़, मक्खन और भस्म मिलाकर शिवलिंग बनाए। शिव भक्तों को पार्थिव शिवलिंग बनाते समय मुख पूर्व या उत्तर में रखें। शिवलिंग की ऊंचाई 8 इंच से ज्यादा न रखें।

पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसे करें

पार्थिव शिवलिंग की पूजा से पहले श्री गणेश, भगवान विष्णु, नवग्रह और देवी पार्वती की आराधना करना चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल, आंकड़ा आदि समर्पित करें। कच्चे गाय के दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें।

पंचमेवा, पंचामृत, मिठाई, फल, धतूरा, भांग आदि का भोग लगाएं और अंत में बाबा भोलेनाथ की आरती उतारें।

हिंदू धर्म में पार्थिव शिवलिंग का महत्व क्या है

शिव पुराण के मुताबिक, पार्थिव शिवलिंग के पूजन से जीवन में आ रही कई समस्याओं का समाधान होता है। इसके अलावा मानसिक और शारीरिक कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। पार्थिव शिवलिंग को लेकर पौराणिक कथा है कि कलयुग में सबसे पहले कूष्माण्ड ऋषि के पुत्र मंडप ने पार्थिव शिवलिंग की पूजा शुरू की थी। पार्थिव शिवलिंग की पूजा के दौरान शिव मंत्रों का जाप करने से समस्त कष्टों का नाश हो जाता है।

शीशे से जुड़ी ये गलतियां घर में लाती हैं दरिद्रता, लगाने से पहले जान लें वास्तु नियम

श्री रोशनी शर्मा
9265235662
हस्त रेखा एवं फेस रीडर (ज्योतिषाचार्य)

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में मौजूद हर वस्तु में ऊर्जा होती है। जिसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव सदस्यों पर पड़ता है। वास्तु में हर चीज को रखने के लिए दिशा निर्धारित है। जिसका पालन करने से घर में सुख-समृद्धि और बरकत आती है। वहीं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे बचना चाहिए। मान्यता है कि इससे घर में नेगेटिव एनर्जी आती है। घर में शीशा लगाते समय वास्तु से जुड़ी बातों का ध्यान रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार, सही दिशा में रखा दर्पण भाग्य के दरवाजे खोलता है। वहीं, गलत दिशा में दर्पण लगाने से घर में दरिद्रता आती है।

दर्पण से संबंधित वास्तु शास्त्र नियम

●दर्पण पश्चिम या दक्षिण की दीवार पर नहीं लगाना चाहिए। इस दिशा में शीशा लगाने से घर में अशांति बनी रहती है।

●घर में शीशा कभी भी टूटा, धुंधला और गंदा नहीं होना चाहिए। ऐसा दर्पण घर में रखने से दरिद्रता आती है। साथ ही सदस्यों की तरक्की रुक जाती है।

● घर के स्टोर रूम में दर्पण नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि इस स्थान पर शीशा रखने से परिवार के सदस्यों को हमेशा मानसिक तनाव रहेगा।

● वास्तु शास्त्र के अनुसार, शयनकक्ष में शीशा नहीं होना चाहिए। वहीं, बिस्तर का प्रतिबिंब दर्पण में नहीं देखना चाहिए। शयनकक्ष के दर्पण में खुद को देखने से भ्रम की स्थिति पैदा होती है।

●वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई में शीशा नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा घर के सदस्यों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर देती है।

● अगर आप चाहते हैं कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो तो मुख्य दरवाजे पर दर्पण न लगाएं।

●वास्तु शास्त्र के अनुसार, यदि आप बाथरूम में शीशा लगा रहे हैं तो उसे पूर्व या उत्तर दिशा की दीवार पर लगाएं।

●दर्पण रखने के लिए पूर्व और उत्तर दिशा शुभ मानी जाती है। उत्तर दिशा भगवान कुबेर का केंद्र है। इसलिए इस दिशा में आईना रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इस उपाय को करने से बिजनेस में समृद्धि आती है।

आखिर किस ग्रह के अशुभ होने से होता है मानसिक तनाव? जानिए उपाय

वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रह है और उसमें से चन्द्रमा को मन का कारक कहा गया है। चन्द्रमा की राशि कर्क जलतत्व है और स्वयं चंद्र भी जलतत्व कारक होकर मनुष्य की भावना का कारक है। शरीर में सबसे अधिक मात्रा जल की है इसलिए मन और बुद्धि दोनों चन्द्रमा से प्रभावित होती है। वैदिक ज्योतिष के विद्वानों के अनुसार किसी कुंडली में अगर चन्द्रमा पाप कर्तरी योग में हो या पीड़ित हो तो जातक का मन कमजोर होता है और उसे जल्द मानसिक तनाव होता है। अमावस्या के करीब जाता हुआ चंद्र कमजोर माना गया है। कृष्ण पक्ष की दशमी से लेकर शुक्ल पक्ष के पंचम तिथि तक के चन्द्रमा के पास बल की कमी होती है इसलिए जातक को चन्द्रमा शुभ परिणाम नहीं दे पाता है। ज्योतिष के विद्वानों ने ऐसी स्थिति में कुछ उपाय भी बताए है जो निम्नलिखित है।

1 - सोमवार के दिन शुभ होरा में गायत्री यंत्र को पूजा घर में स्थापित करें और मोती की माला को गले में धारण करें।

2 - घर के सभी लोग पूर्व दिशा की ओर सिरहाना करने सोए और सोने से पहले कमरे में कर्पूर का एक छोटा सा टुकड़ा जला दे।

3 - जब आप सोने जा रहे है तो हनुमान जी का स्मरण कर हनुमान चालीसा बगल में रखें। यह उपाय शुक्ल पक्ष के मंगल से शुरू करना है। 9 मंगलवार होते ही आपको असर दिखाई देगा।

4 - रात को सोते समय चांदी के गिलास में पानी भरकर रख दे। फिर अगली सुबह उठकर उस पानी को गुलाब के पेड़ की जड़ में डाल दिजिये। इससे धीरे 2 आपका तनाव कम होगा।

5 - कच्चे दूध में चीनी मिलाकर जामुन के पेड़ की जड़ में डालें। यह उपाय आपको शुक्ल पक्ष से शनिवार से शुरू करना है और रोज करना है। इसके अलावा हर अमावस्या की शाम को मंदिर में खीर अर्पित करें। इससे आपको फायदा मिलेगा।

विश्व बैंक के चीफ अजय बंगा ने वित्त मंत्री से की मुलाकात, कह दी ये बड़ी बात, पूरी डिटेल

नई दिल्ली। एजेंसी

विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने बुधवार को कहा कि वैश्विक सुस्ती के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को उसकी घरेलू खपत से स्वाभाविक सहारा मिल रहा है क्योंकि देश की जीडीपी का बड़ा हिस्सा घरेलू मांग पर आधारित है। बंगा ने यहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने जी20 सम्मेलन और भारत एवं विश्व बैंक के बीच सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।

उन्होंने कहा, 'हमने जी20 बैठक से जुड़े बिंदुओं पर चर्चा की। हमने इस बात पर भी चर्चा की कि विश्व बैंक और भारत किस तरह से जी20 से इतर भी काम कर सकते हैं। विश्व बैंक के लिए भारत पोर्टफोलियो के लिहाज से सबसे बड़ा बाजार है और हमारे तमाम हित यहां से जुड़े हैं।' जी20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की गांधीनगर में बैठक संपन्न हुई है। इसमें विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष जैसे बहुपक्षीय विकास संस्थानों की भूमिका पर भी चर्चा हुई।

विश्व बैंक का प्रमुख बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बंगा इस समय भारत की यात्रा पर हैं। उन्होंने जून की शुरुआत में इस अंतरराष्ट्रीय संगठन की कमान संभाली थी। बंगा ने विश्व अर्थव्यवस्था के परिदृश्य पर कहा कि अगले साल की शुरुआत में सुस्ती को लेकर अधिक जोखिम दिख रहा है। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था को अपनी घरेलू खपत के दम पर राहत मिल सकती है। बंगा ने कहा, 'भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का बड़ा हिस्सा घरेलू खपत से आता है। ऐसे में अगर कुछ महीनों के लिए दुनिया में सुस्ती आती है तो भी घरेलू खपत पर आधारित होना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए स्वाभाविक सहारा होगा।'विश्व अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बंगा ने कहा, 'मुझे लगता है कि हमने सोच से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन मेरा अब भी मानना है कि अगले साल की शुरुआत में सुस्ती को लेकर अधिक जोखिम है। मैंने जी20 बैठक में भी कहा कि पूर्वानुमान किस्मत नहीं हैं और आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि पूर्वानुमान सही ही होते हैं।' बंगा ने दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान एक कौशल विकास केंद्र का भी दौरा किया जहां पर उन्होंने छात्रों के साथ कई मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान बंगा ने संवाददाताओं से कहा कि भारत कोविड महामारी के समय पैदा हुई चुनौतियों से मजबूत बनकर उभरा है, लेकिन उसे यह रफ्तार आगे भी कायम रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक सुस्ती के दौर में कई ऐसे कदम उठा रहा है जो उसे आगे रखने में मदद कर रहे हैं।उच्च आय वाली नौकरियों में संभावित वृद्धि के बारे में पूछे जाने पर बंगा ने कहा, ''हमें यह समझना होगा कि ये नौकरियां कहां हैं। ये नौकरियां प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हैं और बहुत कम संख्या में हैं। फिर विनिर्माण क्षेत्र में ऐसी नौकरियां हैं। भारत के सामने फिलहाल मौका है कि वह 'चीन प्लस वन' रणनीति का फायदा उठाए।'' 'चीन प्लस वन' रणनीति के तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने विनिर्माण केंद्र के तौर पर चीन के साथ किसी अन्य देश को भी जोड़ना चाहती हैं। इसके लिए भारत भी एक संभावित दावेदार के तौर पर उभरकर सामने आया है। बंगा ने कहा, ''भारत को यह ध्यान रखना होगा कि इस रणनीति से पैदा होने वाला अवसर उसे 10 साल तक नहीं मिलता रहेगा। यह तीन से लेकर पांच साल तक उपलब्ध रहने वाला अवसर है जिसमें आपूर्ति श्रृंखला को अन्य देश में ले जाने या चीन के साथ अन्य देश को जोड़ने की जरूरत है।''

रियलमी ने रियलमी सी53 और रियलमी पैड 2 का अनावरण किया

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

सबसे भरोसेमंद स्मार्टफोन सेवा प्रदाता रियलमी ने रियलमी सी53 के लॉंच की घोषणा की। यह इसकी चैंपियन सीरीज का नया सदस्य है इसके अलावा युवाओं के लिए परफेक्ट पैड रियलमी पैड 2 भी लॉंच किया गया। अत्याधुनिक फीचर्स लीप फॉरवर्ड टेक्नोलॉजिकल उन्नति, और शक्तिशाली परफॉरमेंस के साथ ये दोनों उत्पाद इस उद्योग में नयी क्रांति ला देंगे। नो लीप नो लॉंच के सिद्धांत के साथ रियलमी उद्योग में उच्च मानक स्थापित कर रहा है यह ब्रांड नये उत्पादों के हर पहलू में लीप फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी पेश करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि यह ग्राहकों को आसानी से मिल सके।

रियलमी सी53 अपने सेगमेंट का पहला और एकमात्र स्मार्टफोन है जिसमें 108एमपी का अल्ट्रा क्लियर कैमरा 3एक्स इन-सेंसर जूम, और 8एमपी सेल्फी कैमरा है। रियलमी सी53 इस मूल्य वर्ग में सबसे बड़ी रोम और डायनामिक रैम के साथ सबसे बड़ा स्टोरेज लेकर आया है। इसमें 12जीबी तक की डायनामिक रैम और 128जीबी की रोम है, जो इस स्मार्टफोन को बिलकुल मक्खन की तरह चलने में मदद करती है। रियलमी सी 53 में 7.99एमएम का अल्ट्रा स्लिम शाइनी चैंपियन डिजाइन और 90हर्ट्ज का डिस्प्ले है तथा इसमें मिनी कैप्सूल फीचर भी है। इस स्मार्टफोन में 5000एमएएच की शक्तिशाली बैटरी और 18वॉट की सुपरवूक चार्जिंग सपोर्ट है यह यूनिसॉक टी612 ऑक्टा-कोर चिपसेट पर चलता है। रियलमी सी53 दो खूबसूरत रंगोंः चैंपियन गोल्ड और चैंपियन ब्लैक में उपलब्ध है और यह दो स्टोरेज वेरिएंट्सः 4जीबी+128जीबी और 6जीबी+64जीबी में आता है।

रियलमी पैड 2 में रियलमी पैड सीरीज का सबसे बड़ा अपग्रेड दिया गया है इसमें सेगमेंट का पहला 11.5' 120 हर्ट्ज 2के डिस्प्ले है जो ज्यादा स्मूथ और आरामदायक अनुभव प्रदान करता है। पिछली जनरेशन के मुकाबले इसमें स्क्रीन टू बॉडी अनुपात 82.5प्रतिशत से बढ़ाकर 85.2प्रतिशत कर दिया गया है। इसकी वजह से डिवाइस का पूरे आकार में ज्यादा बड़ा डिस्प्ले एरिया मिलता है। अपने सबसे ज्यादा स्क्रीन टू बॉडी अनुपात के कारण यह टेबलेट अपने सेगमेंट में लीडर है। इसमें 8630एमएएच की बैटरी लगी है, जो सेगमेंट में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है तथा सेगमेंट का एकमात्र 33 वॉट का फास्ट चार्ज दिया गया है स्टोरेज की बात करें तो रियलमी पैड 2 में 8जीबी+256जीबी तक की सेगमेंट में सबसे ज्यादा मेमोरी है। डायनामिक रैम एक्सपैंशन टेक्नोलॉजी के साथ रियलमी पैड 2 8जीबी रैम को 8जीबी और बढ़ाकर 16जीबी रैम का अनुभव प्रदान कर सकता है। रियलमी पैड 2 में सॉफ्टवेयर में काफी अपग्रेड कर दिया गया है और यह बॉक्स में एंड्रॉयड 13 पर आधारित रियलमी यूआई 4.0 के साथ आने वाला पहला टेबलेट है। यह रियलमी.कॉम, फ्लिपकार्ट और मेनलाइन चैनल्स पर मिलेगा।

भारत में एंट्री को बेताब मस्क की टेस्ला

देश में बनाएगी इलेक्ट्रिक कार, कीमत अमेरिका से रु. 15 लाख कम

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी टेस्ला भारत आने को लंबे वक्त से बेताब है। पहले भी कई बार चर्चाएं तेज हुई, लेकिन हर बार मामला अटक गया। एक बार फिर से इसे लेकर बातचीत शुरू हुई है। बीते महीने जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अमेरिका गए थे, वहां टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने उनसे मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद एक बार फिर भारत में टेस्ला के प्रवेश को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि इस बार बातचीत सकारात्मक दिशा में है और सराकर टेस्ला के प्रस्ताव पर चर्चा कर सकती है। अगर सब ठीक रहा तो जल्द ही भारत में टेस्ला की कारें बिकने लगेंगी।

भारत आने की तैयारी में टेस्ला

लंबे वक्त से टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारों की भारत में लॉन्च को लेकर चर्चाएं होती रही है। इस दिशा में एक बार फिर से टेस्ला और भारत सरकार के बीच बातचीत शुरू हुई है। टेस्ला के प्रतिनिधि भारतीय अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। माना जा रहा है कि टेस्ला भारत में प्लांट लगाकार कार का प्रोडक्शन करने की तैयारी कर रहा है। एलन मस्क की टीम इसके लिए सरकार से बातचीत कर रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला भारत में 5 लाख इलेक्ट्रिक्ल व्हीक्स की सालान कैपेसिटी के साथ फैक्ट्री लगाना चाहती है। इसके लिए वो सरकार से बातचीत कर रही है। टेस्ला ने इन कारों की कीमतों को लेकर भी जानकारी दे दी है। कंपनी ने कहा है कि वो भारत के लिए किफायती इलेक्ट्रिक कारों का प्रोडक्शन कर उसे बेचेगी। भारत में टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारों की कीमत 20 लाख रुपये होगी। ये इलेक्ट्रिक कार की शुरुआती कीमत होगी।

अमेरिका से सस्ती

अमेरिका में टेस्ला कार की शुरुआती कीमत 43490 डॉलर यानी करीब 35.65 लाख रुपये है। वहीं भारत में टेस्ला कारों की कीमत 20 लाख रुपये से शुरू होगी। यानी अमेरिका के मुकाबले भारत में टेस्ला की गाड़ियां 15 से 16 लाख रुपये सस्ती होगी। टेस्ला भारत को एक बड़े बाजार के तौर पर देख रहा है। चीन में इसकी मजबूत उपस्थिति है, लेकिन अब वो भारत को एक्सपोर्ट बेस के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। कंपनी इंडो-पैसिफिक रीजन में टेस्टा की कारों को एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इस बात भारत सरकार और टेस्ला के बीच बात बन जाएगी। क्योंकि टेस्ला इस बार बेहतर योजना के साथ आई है। स्थानीय विनिर्माण और एक्सपोर्ट को शामिल कर टेस्ला ने इस राह से बड़े रोड़े को खत्म कर दिया है। एलन मस्क के प्रतिनिधियों और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की बातचीत चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि बात बन जाएगी। हालांकि अभी दोनों में से किसी की ओर से आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। भारत में टेस्ला की इंट्री ने टाटा, हुडई, मारुति जैसी ऑटोमोबाइल कंपनियों की परेशानी बढ़ेगी। उनके लिए टेस्ला से मुकाबला करना आसान नहीं होगा।

स्मार्ट गैजेट्स में देसी कंपनियों का जलवा, 'मेड इन इंडिया' को मिल रहा बूस्ट

नई दिल्ली। एजेंसी

हियरेबल, वियरेबल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेज जैसे स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ ईयरबड्स, नेकबैंड, स्मार्ट स्पीकर का भारत में मार्केट बढ़ रहा है। इसमें बड़ा योगदान भारत के घरेलू ब्रैंड्स का है। इसकी वजह है देसी ब्रैंड पर भारतीयों को बढ़ता भरोसा, नए लॉन्च, अलग-अलग चैनलों पर छूट और ब्रैंड्स की बेहतर मार्केटिंग। यह कहना है जेटवेर्क के को-फाउंडर राहुल शर्मा का। राहुल शर्मा ने कहा कि इंडियन बैंड्स कम कीमत पर बेहतर फीचर वाले और टिकाऊ डिवाइस बाजार में उतार रहे हैं। इसकी वजह से इन पर ग्राहकों का भरोसा भी बढ़ रहा है, साथ ही मेड इन इंडिया को बूस्ट भी मिल रहा है। इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन (IDC) की हालिया रिपोर्ट भी इस बात की तस्दीक करती है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में इस साल की पहली तिमाही में 2.5 करोड़ से अधिक वियरेबल डिवाइसेज की शिपमेंट हुई है। यह पिछले साल के मुकाबले 80 फीसदी ज्यादा है। इस सेगमेंट में स्मार्टवॉच सबसे तेजी से बढ़ने वाली कैटिगरी रही। इसमें लगभग 1.04 करोड़ यूनिट्स की शिपमेंट हुई।राहुल शर्मा ने बताया कि जेटवेर्क का सबब्रैंड जेट टाउस इंडिया वियरेबल्स, हियरेबल्स,0 और इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (आईओटी) की 2.5 करोड यूनिट्स इस साल तैयार करेगी। कई देसी और विदेशी ब्रैंड्स के लिए कंपनी डिवाइस बना रही है। स्मार्ट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस निर्माता कंपनी जेट टाउन का 2022 में ऑपरेशन शुरू हुआ। फाइनैंशल ईयर 2022-2023 में 250 करोड़ रुपये रेवेन्यू कंपनी को मिला। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी 1000 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रही है। राहुल ने बताया कि देश स्मार्ट गैजेट्स बनाने के मामले में तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है। बड़ी-बड़ी कंपनियां अब देश में प्रोडक्शन यूनिट शुरू कर चुकी हैं। जो देश की इकॉनमी के लिए अच्छा संकेत है। बाजार में कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, अब कम कीमत में बेहतर फीचर्स देने की रेस है, इससे ग्राहकों को भी फायदा मिल रहा है।

जम्मू-कश्मीर की लुप्त होती नमदा आर्ट को पुनर्जीवित कर रहा स्किल इंडिया प्रोजेक्ट

प्रोजेक्ट के तहत छह जिलों के लगभग 2,200 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के स्किल इंडिया के पायलट प्रोजेक्ट के तहत कश्मीर के नमदा क्राफ्ट को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया जा रहा है, जिसमें राज्य के छह जिलों के लगभग 2,200 उम्मीदवार प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री, श्री राजीव चंद्रशेखर ने आज यूनाइटेड किंगडम (यूके) में एक्सपोर्ट के लिए नमदा क्राफ्ट के उत्पादों के पहले बैच को हरी झंडी दिखाई। यह प्रोजेक्ट कौशल विकास के क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल का एक बड़ा उदाहरण स्थापित करता है, क्योंकि इसे स्थानीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है।

इस पहल के तहत, लगभग 2,200 उम्मीदवारों को नमदा क्राफ्ट में प्रशिक्षित किया गया है, जो इस पारंपरिक क्राफ्ट को संरक्षित करने और स्थानीय बुनकरों और कारीगरों को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस प्रोजेक्ट के द्वारा कश्मीर के छह जिलों, श्रीनगर, बारामूला, गांदरबल, बांदीपोरा, बडगाम और अनंतनाग में लोगों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत के युवाओं की स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दृढ़ बनी हुई है। मीर हैंडीक्राफ्ट और श्रीनगर कारपेट ट्रेनिंग और मार्केट सेन्टर जैसे स्थानीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से जम्मू-कश्मीर में इस पायलट प्रोजेक्ट का सफल कार्यान्वयन, कौशल विकास को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास के लिए निवेश आकर्षित करने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की ताकत का जीवंत उदाहरण है।

इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए, कौशल विकास और उद्यमशीलता और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के राज्य मंत्री, श्री राजीव चन्द्रशेखर ने कहा, 'हमने 2021 में नमदा परियोजना शुरू की थी, और अब इसके परिणाम को देखना बेहद संतोषजनक है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नया भारत, नए अवसर, नई समृद्धि के विज़न के साथ पूरी तरह से मेल खाता है और जो इस बात पर जोर देता है कि कौशल का मतलब नए अवसर और नई समृद्धि पैदा करना है।

डीएसपी म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया डीएसपी एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स ईटीएफ

निवेशकों के लिए भारत की ग्रोथ स्टोरी और पीएसयू बैंकों के रिवाइवल में हिस्सा लेने का अवसर

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

डीएसपी म्यूचुअल फंड ने तीन ओपन-एंडेड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) डीएसपी एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स ईटीएफ, डीएसपी निफ्टी प्राइवेट बैंक ईटीएफ और डीएसपी निफ्टी पीएसयू बैंक ईटीएफ लॉन्च करने की घोषणा की। डीएसपी एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स ईटीएफ एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स को ट्रैक करता है और निवेशकों को अनुकूल इकोनॉमिक एंड कैपेक्स कंडीशंस वाली सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत के बाजारों में निवेश करने का अवसर प्रदान करता है। डीएसपी निफ्टी प्राइवेट बैंक ईटीएफ निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स को ट्रैक करता है, जो निवेशकों को भारतीय प्राइवेट बैंकों के लंबे समय के स्ट्रक्चरल ग्रोथ कह कहानी में हिस्सा लेने का मौका देता है। डीएसपी निफ्टी पीएसयू बैंक ईटीएफ निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स को ट्रैक करता है और निवेशकों को पीएसयू बैंकों के रिवाइवल में दांव लगाने का मौका देता है। एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स

इंडेक्स लंबी अवधि में कमाई पर बारीकी से नजर रखता है और यह मौजूदा अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने के लिए सेक्टर के रुझान और रोटेशन को पकड़ता है। इस इंडेक्स को विभिन्न क्षेत्रों में डायवर्स किया गया है और इसमें लार्ज-कैप ओरिएंटेशन है। सूचकांक का एक लंबा इतिहास भी है, जिसमें पुराने डेटा से पता चलता है कि जैसे-जैसे होल्डिंग अवधि बढ़ती है, नकारात्मक रिटर्न की आशंका कम हो जाती है, और तुलनात्मक रूप से उच्च रिटर्न की संभावना बढ़ जाती है। भारत में प्राइवेट बैंक एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ की कहानी रहे हैं और पिछले 18 वर्षों में इन बैंकों की बाजार हिस्सेदारी दोगुनी हो गई है। प्राइवेट सेक्टर के बैंकों की बैलेंस शीट भी मजबूत हो गई है और उनके पास लगातार आ रहे डिपॉजिट और कर्ज की वृद्धि को सपोर्ट करने के लिए अच्छे से पूंजी है। प्राइवेट बैंकों का वित्तीय अनुपात भी पिछले तीन सालों से तेजी से बढ़ रहा है, जबकि उनका मूल्यांकन उनके ऐतिहासिक औसत की तुलना में आकर्षक स्तर पर है। इन बैंकों के लिए कर्ज और जमा की वृद्धि भी मजबूत दर से बढ़ रही है, जबकि नेट एनपीए 8 साल के निचले स्तर पर है। पीएसयू बैंकों के लिए, उनके रिवाइवल की कहानी शायद पिछले तीन सालों से शुरू हुई, जब पीएसयू बैंक प्रदर्शन में निजी बैंकों को मात देने लग गए। पीएसयू बैंकों ने एनपीए में गिरावट और अधिक रिकवरी से अपने शुद्ध ब्याज मार्जिन में भी सुधार किया है। पीएसयू बैंकों के विलय से उनकी बैलेंस शीट और क्रेडिट ग्रोथ भी मजबूत हुई है। पीएसयू बैंकों का मौजूदा मूल्यांकन इसके ऐतिहासिक औसत से नीचे है। एसेट पर इसके बढ़ते रिटर्न को देखते हुए यह क्षेत्र री-रेटिंग के लिए तैयार दिख रहा है। डीएसपी एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स ईटीएफ, डीएसपी निफ्टी प्राइवेट बैंक ईटीएफ और डीएसपी निफ्टी पीएसयू बैंक ईटीएफ के लिए नया फंड ऑफर 17 जुलाई 2023 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 21 जुलाई 2023 को बंद होगा।

मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के तहत 12वें क्वालिटी मार्क अवाड्र्स 2023 का आयोजन

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

मेक इन इंडिया की अवधारणा के तहत बीते दिनों डबल ट्री बाय हिल्टन, अहमदाबाद में कवोलीटी मार्क ट्रस्ट द्वारा ' कवोलीटी मार्क अवाड्र्स' का आयोजन किया गया, जो इस वर्ष इसका बारहवां संस्करण है, इस वर्ष कवोलीटी मार्क ट्रस्ट ने 40 से अधिक उद्यमियों को सम्मानित किया। कवोलीटी मार्क अवाड्र्स 2023 में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर, भाग लिया। साथ ही इस कार्यक्रम में बॉलीवुड से सेलिब्रिटी गेस्ट मिस्टर गुलशन ग्रोवर भी मौजूद रहे। समारोह में भारत के सबसे प्रतिष्ठित संगठनों के प्रतिनिधि श्री नंदीश शुक्ला - उप निदेशक ने भाग लिया। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष, डॉ. सौरभ पारधी- टीसीजीएल के प्रबंध निदेशक, कर्नल हेमंत कपूर - राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर ।

कवोलीटी मार्क ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री हेतलभाई ठक्कर से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि इस वर्ष यह समारोह लोगों के सहयोग से हुआ और विशेष रूप से उन्होंने पुष्पक लॉजिस्टिक के श्री राहुल मोदी को उनके पूरे समर्थन के लिए विशेष धन्यवाद दिया। उन्होंने यह भी बताया कि ' कवोलीटी मार्क अवाड्र्स' में भारत के 16 राज्यों के 600 से अधिक उद्यमियों ने भाग लिया है। उद्योग के अलावा, महिला उद्यमियों और सेवा उद्योग के व्यक्तियों ने भी ' कवोलीटी मार्क अवाड्र्स' में भाग लिया, जिनमें से जूरी सदस्यों द्वारा इस वर्ष 41 उद्यमियों का सम्मानित किया गया।

भाई-भाई फेम, श्री अरविंद वेगड़ा, जो संगठन के उपाध्यक्ष हैं, बातचीत में उन्होंने आगे कहा कि सभी सलाहकार समिति के सदस्यों और विशेष रूप से सिक्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के श्री जयंतीभाई कुंभानी और पूजा इंफ्रा के श्री केतन सेठ को इस वर्ष कवोलीटी मार्क अवाड्र्स में उनके आवश्यक योगदान के लिए धन्यवाद। कवोलीटी मार्क के इवेंट डायरेक्टर श्री विवेक ठक्कर ने इस कार्यक्रम को बहुत सुचारू रूप से प्रबंधित किया और सभी प्रतिभागी कवोलीटी मार्क द्वारा बनाए गए प्रेजेंटेशन वीडियो से बहुत खुश हुए।

भारत और चीन के बीच व्यापार में आई गिरावट, वर्षों बाद हुआ यह कारनामा, आखिर क्या है वजह?

नई दिल्ली। एजेंसी

सीमा पर तनाव के बावजूद पिछले कुछ वर्षों में भारत-चीन के बीच व्यापार काफी बढ़ा है। लेकिन अब वर्षों बाद इंडिया-चाइना ट्रेड में गिरावट के संकेत देखे जा सकते हैं। इस साल की पहली छमाही में भारत और चीन के बीच व्यापार में 0.9 फीसदी की गिरावट आई है। हालांकि, ऐसा तब हुआ है, जब चीन के कुल विदेशी व्यापार में करीब 5 फीसदी की गिरावट आई है। कोरोना महामारी के प्रकोप से रिकवर होने में चीनी इकॉनमी को स्ट्रगल करना पड़ा है। यही कारण था कि उसका विदेशी व्यापार गिरा है।

0.9 फीसदी कम रहा भारत को चीन का निर्यात

इस साल की पहली छमाही में भारत को चीन का निर्यात 56.53 अरब डॉलर का रहा। यह एक साल पहले के 57.51 अरब डॉलर से 0.9 फीसदी कम है। गुरुवार को चीनी कस्टम्स द्वारा जारी आंकड़ों से यह जानकार मिली है। चीन को भारत का निर्यात इस अवधि में कुल 9.49 अरब डॉलर रहा। यह एक साल पहले 9.57 अरब डॉलर रहा था। इस तरह साल 2023 की पहली छमाही में व्यापार घाटा एक साल पहले के 67.08 अरब डॉलर से घटकर 47.04 अरब डॉलर रह गया। पिछला साल भारत-चीन व्यापार के लिए बंपर ईयर रहा था। यह पिछले साल 135.98 अरब डॉलर के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। साल 2022 में कुल भारत-चीन व्यापार 8.4 फीसदी की बढ़त के साथ एक साल पहले के 125 अरब के आंकड़े को पार कर गया था।

पहली बार 100 अरब डॉलर गया था व्यापार घाटा

द्विपक्षीय संबंधों में उतार-चढ़ाव के बावजूद चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया था। साल 2022 में भारत के लिए व्यापार घाटा 101.02 अरब डॉलर रहा। यह 2021 में 69.38 अरब डॉलर था। वहीं, इस साल की पहली छमाही में भारत-चीन व्यापार में वर्षों बाद गिरावट देखने को मिली है। क्योंकि इस दौरान आयात और निर्यात सहित चीन का कुल व्यापार एक साल पहले की तुलना में 5 फीसदी गिर गया था। निर्यात 3.2 फीसदी गिरा और आयात में 6.7 फीसदी की गिरावट आई।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित । संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।